



2026:AHC:67737-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील दोषपूर्ण सं. - 225 वर्ष 2026

प्रबंधन समिति, श्री गांधी इंटर कॉलेज हरपुर बुध अपीलकर्ता

बनाम

यूपी और 2 अन्य प्रतिपक्षी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: आस्था मिश्रा, अवनीश त्रिपाठी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रमेश चंद्र द्विवेदी

न्यायालय सं - 3

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी

संदर्भ: दीवानी विविध माफी आवेदन संख्या-01 वर्ष 2026

1. यह अपील आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति जमा नहीं करने के लिए छूट आवेदन के साथ दायर की गई है।
2. तदनुसार, छूट आवेदन की अनुमति है। दोष ठीक हो जाते हैं।

अपील पर आदेश

3. श्री राधा कांत ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अवनीश त्रिपाठी, मूल याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता के अधिवक्ता, श्री राजीव गुप्ता, राज्य प्रतिपक्षियों के अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्री रमेश चंद्र द्विवेदी, निजी-प्रतिपक्षियों के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
4. वर्तमान अंतर-न्यायालय अपील एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17.02.2026 को प्रबंधन समिति श्री गांधी इंटर कॉलेज हरपुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य, 2026:AHC:34506 में पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ उत्पन्न हुई है। उस आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा, एकल न्यायाधीश ने प्रबंधन समिति/मूल याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को दोष के कारण खारिज कर दिया है- कि रिट याचिका प्रबंधन समिति द्वारा श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ला (जिन्होंने खुद को उक्त प्रबंधन समिति के प्रबंधक के रूप में वर्णित किया था) के माध्यम से दायर की गई थी, जो उक्त तारकेश्वर प्रसाद शुक्ला के पक्ष में प्रबंधन समिति के प्रस्ताव द्वारा समर्थित नहीं थी।

5. हालांकि, इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि उक्त श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ला श्री गांधी इंटर कॉलेज, हापुड़ की प्रबंधन समिति के प्रबंधक हैं, रिट याचिका को सुनवाई योग्य नहीं पाया गया है क्योंकि यह उनके पक्ष में किसी भी प्रस्ताव द्वारा समर्थित नहीं था।

6. एकल न्यायाधीश ने आगे तर्क दिया है कि पूरक हलफनामे के साथ दायर 13.01.2026 को बाद का संकल्प कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

7. श्री आर.के. ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 6 के आधार पर प्रस्तुत करेंगे, जिसे प्रशासन की योजना के खंड 20(3) सपठित किया गया है, जैसा कि उक्त संस्था पर लागू होता है, प्रबंधन समिति के प्रबंधक को प्रबंधन समिति की ओर से रिट याचिका दायर करने के लिए अधिकृत किया गया था।

8. उमेश चंद्रा और अन्य बनाम महिला विद्यालय सोसायटी, अमीनाबाद, लखनऊ और अन्य, 2006 (24) एलसीडी 1373 में एक समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए, प्रशासन की योजना के सक्षम खंड 20(3)(9) के सामने, श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ला, प्रबंधन समिति के प्रबंधक के रूप में, रिट याचिका को स्थापित करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया था, यह दृढ़ता से आग्रह किया गया है।

9. साथ ही, रिट याचिका को बनाए रखने के लिए प्रबंधन समिति के प्रस्ताव को उनके पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी। वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया गया है, किसी भी मामले में, पूरक हलफनामे के माध्यम से, 13.01.2026 के आगे के संकल्प को अभिलेखों पर लाया गया था। यह स्पष्ट रूप से प्रबंधन समिति के प्रबंधक श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ला को रिट याचिका दायर करने के



लिए अधिकृत करता है। एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि पूरक हलफनामा और उसके साथ दायर किया गया संकल्प, कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, अस्थिर है।

10. श्री आर.के. ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करेंगे, इस संबंध में कानून काफी अच्छी तरह से तय है। यदि प्रशासन की योजना स्वयं प्रबंधन समिति के किसी भी पदाधिकारी को प्रबंधन समिति के लिए और उसकी ओर से किसी भी कानूनी कार्यवाही को स्थापित करने या बचाव करने के लिए अधिकृत करती है, तो न्यायालय कभी भी ऐसी प्रबंधन समिति को ऐसे विधिवत अधिकृत व्यक्तियों के पक्ष में विशिष्ट प्रस्ताव पारित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं-स्थापित करने या व्यक्तिगत कार्यवाही का बचाव करने के लिए। यदि एकल न्यायाधीश द्वारा रजिस्ट्री को जारी किए गए निर्देश को लागू किया जाता है, तो इससे अनावश्यक जटिलताएं और देरी हो सकती है क्योंकि न्याय तक पहुंच में बाधा उत्पन्न हो सकती है, बिना किसी उद्देश्य के किसी भी उद्देश्य के जो किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती है।

11. दूसरी ओर, श्री रमेश चंद्र द्विवेदी प्रस्तुत करेंगे, जबकि उमेश चंद्र (उपरोक्त) में समन्वय पीठ द्वारा प्रतिपादित सही सिद्धांत और कानून के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है, उस सिद्धांत को प्रत्येक मामले के व्यक्तिगत तथ्यों को देखते हुए लागू किया जाना है। प्रशासन की योजना के खंड 20(3)(9) का उल्लेख करते हुए, वह प्रस्तुत करेंगे कि प्रबंधन समिति के प्रबंधक को प्रबंधन समिति की ओर से कानूनी कार्यवाही शुरू करने और बचाव करने के लिए प्रशासन की योजना द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है। उन्हें केवल प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व करने और दलीलों पर हस्ताक्षर करने और दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत किया गया है। जब तक प्रबंधन समिति किसी विशेष कानूनी कार्यवाही को स्थापित करने या बचाव करने के लिए एक विशिष्ट प्रस्ताव पारित नहीं करती है, तब तक प्रबंधन समिति का प्रबंधक स्वतंत्र रूप से अपने दम पर कार्य नहीं कर सकता है। दिनांक 13.01.2026 के बाद के संकल्प के अस्तित्व के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है, उक्त प्रस्ताव कानून के अनुसार पारित नहीं किया गया है।



12. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, सबसे पहले, अधिनियम की धारा 6 निम्नानुसार पढ़ती है:

"6. सोसाइटियों द्वारा और विपक्ष में वाद-इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रत्येक सोसायटी अध्यक्ष, अध्यक्ष, या प्रधान सचिव, या न्यासी के नाम पर मुकदमा कर सकेगी या मुकदमा दायर कर सकेगी, जैसा कि सोसायटी के नियमों और विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और, ऐसे निर्धारण के उल्लंघन में, ऐसे व्यक्तियों के नाम पर जो इस अवसर के लिए शासी निकाय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे:

परन्तु यह किसी भी व्यक्ति के लिए सक्षम होगा जो सोसायटी के विरुद्ध दावा या मांग करता है, अध्यक्ष या अध्यक्ष, या प्रधान सचिव या उसके न्यासी पर मुकदमा दायर करने के लिए, यदि शासी निकाय को आवेदन पर कोई अन्य अधिकारी या व्यक्ति प्रतिपक्षी के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

13. प्रशासन की योजना के खंड 20(3)(2) और (9) जहां तक यह यहां प्रासंगिक है, नीचे दिया गया है:

"20. प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य-

(3) प्रबंधक

2. समिति के निर्देशों के अधीन रहते हुए संस्था के समस्त सम्पत्तियों तथा धनराशियों के प्रबंध तथा प्रशासन केलिए उत्तरदायी होगा

9. संस्था को संबंधित मामलों में समिति संस्था तथा सभा की समस्त कानूनी कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करना और उनकी कार्यवाहियों तथा मामलों में उनकी ओर से अभिकथनो (प्लीडिंग्स) पर हस्ताक्षर करना तथा उन्हें सन्हीं त्थापित करना।"

14. तथ्यों के अनुसार, कोई विवाद नहीं है। प्रशासन की योजना के उक्त खंड के बल पर याचिका दायर की गई थी, प्रबंधन समिति द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव पर भरोसा किए बिना। उठाई जा रही आपत्ति पर, मूल याचिकाकर्ता/प्रबंधन समिति/अपीलकर्ता द्वारा पूरक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें दिनांक 13.01.2026 के संकल्प को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभिलेखों पर लाने के लिए श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ला, प्रबंधक, को कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था, जो प्रबंधन समिति के अनुसार, उक्त तारकेश्वर प्रसाद शुक्ला को अन्यथा प्रशासन की योजना स्थापित करने के लिए अधिकृत किया गया था। उस सीमा तक, दिनांक 13.01.2026 का संकल्प प्रबंधन समिति द्वारा स्पष्टीकरण देने के लिए जारी किया गया प्रतीत होता है।

15. जहां तक उमेश चंद्र (उपरोक्त) में समन्वय पीठ के निर्णय का संबंध है, इसने निम्नलिखित मुद्दे तय किए थे:

"क्या प्रबंधन समिति या किसी सोसायटी की आम सभा के किसी भी संकल्प के अभाव में, उसके पदाधिकारी द्वारा (प्रस्तुत मामले में) एक रिट याचिका दायर की जा सकती है। सोसायटी के सचिव) को सोसायटी के कारण की पैरवी करने के लिए?"

16. उस मामले में, प्रशासन की योजना के खंड 20(3)(9) के समानांतर या समकक्ष कोई प्रावधान नहीं था, जो प्रस्तुत मामले में लागू होता है। कानून के विस्तृत विश्लेषण के बाद, समन्वय पीठ ने अपने निष्कर्षों को नीचे दर्ज किया:

"68. उपरोक्त को देखते हुए, हम अपने निष्कर्ष को निम्नानुसार दर्ज करने के लिए आगे बढ़ते हैं:

(i) अधिनियम की धारा 6 में प्रयुक्त शब्द "निर्धारण" या "निर्धारण" का अर्थ है कि सोसायटी के नियमों, उपनियमों या संविधान को तैयार करते समय, सोसायटी के सामान्य निकाय को इस मामले पर चर्चा करके नियमों में विशेष रूप से प्रावधान करना चाहिए कि सोसायटी का प्रतिनिधित्व करने वाला मुकदमा स्थापित करने के लिए कौन अधिकृत होगा। किसी सोसायटी के नियमों के तहत ऐसे विशिष्ट प्रावधानों के अभाव में यह निर्धारित करना प्रबंधन समिति या शासी निकाय के लिए है कि एक वाद की स्थापना के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में सोसायटी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। केवल एक व्यक्ति जो नियमों द्वारा या शासी निकाय या कार्यकारी निकाय द्वारा एक वाद स्थापित करने के लिए



अधिकृत है, इस न्यायालय में या अन्य न्यायालयों या न्यायाधिकरणों में एक वाद या याचिका दायर करने का हकदार होगा।

(ii) अधिनियम की धारा 6 के तहत, नियम या उपनियम बनाते समय किसी सोसायटी के सदस्यों पर यह दायित्व होगा कि वे स्पष्ट रूप से यह उपबंध करें कि प्रतिनिधि क्षमता में सोसायटी की ओर से मुकदमा करने का हकदार कौन होगा। सोसायटी के नियमों या उपनियमों में स्पष्ट उपबंध के अभाव में, अध्यक्ष, सचिव या प्रबंधक या अध्यक्ष जैसे कोई भी पदाधिकारी कोई भी वाद दायर करने या प्रतिनिधि क्षमता में आपत्ति दर्ज करने का हकदार नहीं होगा। किसी पदाधिकारी को केवल प्रशासनिक या कार्यकारी शक्ति प्रदान करना अधिनियम की धारा 6 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

(iii) अधिनियम के तहत गठित सोसायटी के नियमों या उपनियमों में विशिष्ट या स्पष्ट उपबंधों के अभाव में, केवल ऐसा व्यक्ति ही उस सोसायटी का प्रतिनिधित्व करने का हकदार होगा जिसे सोसायटी के शासी निकाय द्वारा इसके संकल्प के माध्यम से विधिवत प्राधिकृत किया जा रहा है।

(iv) विधिवत रूप से सशक्त व्यक्ति द्वारा दायर की गई याचिका या वाद केवल तभी सुनवाई योग्य होगी जब वह अपने उद्देश्यों और उद्देश्यों या नियमों के अनुरूप या प्रबंधन समिति के संकल्प के अनुसार समाज के कारण का प्रतिनिधित्व करने के लिए दायर की जा रही हो। किसी याचिका या वाद में इस तरह की विशिष्ट दलील के अभाव में, ऐसा वाद या याचिका बनाए रखने योग्य नहीं होगी।

(v) ...

(vi) ...

(vii) ...

(ix) ...



(x) ...

(

म

ह

त्व

स

न्नि

वि

ष्ट

)

17. जिस हद तक, कोई विपरीत कानून अस्तित्व में नहीं दिखाया गया है और आगे हम उस निर्णय में दर्ज समन्वय पीठ के तर्क से पूरी तरह सहमत हैं, हमने केवल संक्षिप्तता के लिए, उस निर्णय में निकाले गए निष्कर्षों का उल्लेख किया है।

18. इस तरह के निष्कर्षों के आधार पर, यह जांच की जानी बाकी है, यदि उमेश चंद्र (उपरोक्त) में निर्धारित कानून के अनुसार, प्रस्तुत मामले में प्रबंधन समिति-मूल याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता को रिट कार्यवाही शुरू करने के लिए उक्त प्रबंधन समिति के प्रबंधक श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ला को अधिकृत करने के लिए प्रबंधन समिति का एक विशिष्ट संकल्प प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने की कोई आवश्यकता थी।

19. बाध्यकारी कानून के अनुसार, प्रस्तुत याचिकाकर्ता जैसे व्यक्ति के लिए, रिट याचिका को स्थापित करने के लिए प्रबंधन समिति के प्रबंधक को अधिकृत करने वाले प्रशासन की योजना में एक्सप्रेस क्लॉज पर भरोसा करना पर्याप्त होगा। यहां, खंड 20(3)(9) के तहत, अन्य बातों के अलावा, प्रबंधन समिति के प्रबंधक को विशेष रूप से सभी कानूनी कार्यवाही में प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व करने और दलीलों पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ इसे सत्यापित करने के लिए अधिकृत किया गया है।



20. एक बार जब इस तरह के अधिकार को प्रशासन की उक्त योजना के तहत प्रबंधक में निहित कर दिया जाता है, तो हमें श्री आरसी द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे प्रतिवाद को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिलता है, कि मुकदमा चलाने के लिए प्रबंधन समिति द्वारा एक विशिष्ट प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता थी।

21. इस हद तक, उक्त खंड अधिनियम की धारा 6 में निहित वैधानिक सिद्धांत का प्रतिबिंब है, जबकि इस बात से अवगत रहते हुए कि यह मुद्दा किसी सोसायटी द्वारा रिट याचिका दायर करने के संबंध में उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि प्रबंधन समिति द्वारा उठाया गया है, हम पाते हैं, श्री आर.सी. द्विवेदी द्वारा उठाई जा रही आपत्ति अति-तकनीकी है।

22. यह एक सामान्य रूप से ज्ञात तथ्य है कि मुकदमेबाजी, कभी-कभी, आकस्मिक स्थितियों में वादी को अत्यंत समीचीनता के साथ कार्य करने के लिए मजबूर करती है। सबसे पहले, प्रशासन की योजना मुकदमेबाजी की संस्था के संबंध में प्रबंधक की शक्तियों पर कोई बंधन नहीं रखती है। खंड 20(3)(2) के विपरीत, यह देखा जाता है, प्रबंधन समिति की संपत्तियों और धन से निपटने के लिए प्रबंधक की शक्तियों के विपरीत, संस्था और बचाव मुकदमेबाजी के संबंध में, प्रबंधन समिति ने उस संबंध में प्रबंधक को निर्देश जारी करने की कोई शक्ति सुरक्षित नहीं की है।

23. इस प्रकार, जहां समाज वांछित हो सकता है, उसने विशेष रूप से प्रबंधन समिति के प्रबंधक के कार्यों को प्रबंधन समिति द्वारा जारी निर्देशों के अधीन किया है। ततस्त्य विपरीत, इसने अन्य क्षेत्रों को इस तरह की बेड़ी से मुक्त छोड़ दिया है और इस प्रकार प्रबंधक को संस्था के सीमित उद्देश्य के लिए अपने दम पर कार्य करने और किसी भी मुकदमेबाजी में रक्षा स्थापित करने में सक्षम बनाया है। हम ध्यान रखते हैं, किसी दिए गए मामले में प्रबंधक द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई, स्पष्ट रूप से प्रबंधन समिति के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के भीतर रहेगी, जो हस्तक्षेप करने या ऐसे प्रबंधक को विशिष्ट निर्देश जारी करने का विकल्प चुन सकती है।

24. दूसरा, हमने यह भी विचार किया है, एक प्रस्ताव पारित करने के प्रयोजनों के लिए, प्रक्रिया प्रशासन की योजना के खंड 14 (3) द्वारा शासित है। सुलभ संदर्भ के लिए, यह नीचे दिया गया है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"14. प्रबन्ध समिति की बैठक

1-साधारण बैठक:- समिति की साधारण बैठक अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रबन्धक द्वारा 4 माह में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जायेगी।

2-आवश्यक बैठक: प्रबन्धक (अध्यक्ष के अनुमोदन से) जब आवश्यक हो समिति की लिखित माँग पर (जिसमें विचार के लिए विशिष्ट विषय या संकल्प का उल्लेख होना चाहिए) समिति की आवश्यक बैठक अवश्य बुलायेगा। यदि अध्यक्ष या प्रबन्धक द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो प्रबन्ध समिति के 6 सदस्यों / पदाधिकारी निरीक्षक की अनुमति से सामूहिक रूप से मिलकर बैठक बुला सकेंगे।

3- बैठक के लिए नोटिस:- समिति की साधारण बैठक के लिए कम से कम पूरे 7 दिन का नोटिस एवं आवश्यक बैठक के लिए कम से कम पूरे 3 दिन का नोटिस दिया जायेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि साधारण बैठक के दिनांक से 10 दिन पूर्व और आवश्यक बैठक के दिनांक से 6 दिन पूर्व सदस्य के अन्तिम जापपते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भेजने पर यह समझा जायेगा कि वह उस सदस्य पर यथोचित समय के भीतर पर्याप्त रूप से तामिल कर दिया गया है, नोटिस के साथ कार्यसूची होगी और उसमें बैठक का दिनांक, स्थान तथा समय दिया रहगा। यदि नोटिस रजिस्टर्ड डाक से नहीं दिया जाता है तो समिति के किसी सदस्य की आपत्ति पर जाँच के उपरान्त निरीक्षक उस बैठक की कार्यवाही को (जैसी स्थिति हो) अवैध या वैध घोषित कर सकेगा।

4- गणपूर्ति एवं स्थगनोपरान्त बैठक: पाँच सदस्यों या तत्कालीन सदस्यों की एक तिहाई संख्या से जो भी अधिक हो समिति की गणपूर्ति होगी। यदि बैठक प्रारम्भ होने के लिए निश्चित समय के पश्चात 30 मिनट तक अपेक्षित गणपूर्ति न हो तो बैठक स्थगित हो जायेगी। बैठक फिर उसी दिन या किसी दूसरे दिन ऐसे समय हो सकती है जिसकी घोषणा अध्यक्ष उक्त 30 मिनट की समाप्ति पर करें।



स्थगनोपरान्त बैठक के लिए गणपूर्ति या किसी अन्य नोटिस की अपेक्षा न होगी किन्तु उस बैठक में किसी ऐसे विषय पर विचार नहीं किया जायेगा जो गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित न रहा हो।

25. स्पष्ट रूप से, प्रबंधन समिति की कोई बैठक नहीं बुलाई जा सकती है और परिणामस्वरूप इसके द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि एक आम बैठक के उद्देश्य से सात दिनों का स्पष्ट नोटिस जारी नहीं किया जाता है और एक तत्काल बैठक के लिए तीन दिनों का स्पष्ट नोटिस जारी नहीं किया जाता है। इसके अलावा, उक्त खंड पंजीकृत डाक द्वारा पूर्व सूचना जारी करने का आदेश देता है। यदि कड़ाई से लागू किया जाता है, तो यह बिना किसी अच्छे कारण के न्याय तक पहुंच के मार्ग में केवल बाधाएं और बाधाएं पैदा करेगा। इसके अलावा, उक्त खंड के अनुपालन के परिणामस्वरूप परिस्थितियों के उत्पन्न होने की स्थिति में और देरी हो सकती है - जिससे बैठक को स्थगित करना पड़ सकता है।

26. इस हद तक, प्रबंधन समिति एक विधिवत निर्वाचित निकाय बनी हुई है और आगे जिस हद तक प्रबंधक प्रबंधन समिति का विधिवत नियुक्त प्राधिकारी है, जो प्रबंधन समिति की ओर से मुकदमेबाजी स्थापित करने और बचाव करने में सक्षम है, सुझाई जा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रही व्याख्या के परिणामस्वरूप उद्देश्यहीन देरी हो सकती है और यहां तक कि न्याय के कारण को भी हराया जा सकता है। अनिवार्यताओं और परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जैसा कि निर्देशित हो सकता है - जब तक कि प्रबंधन समिति बिना किसी देरी के वास्तविक समय में कार्यवाही स्थापित करने या / और बचाव करने में सक्षम नहीं है, प्रबंधन समिति और समाज स्वयं नुकसान उठाने के जोखिम में खड़े हो सकते हैं, चाहे वह अपूरणीय हो या भारी देनदारियों को शामिल करता हो, आदि।

27. इसलिए, कानून का ठोस अनुपालन पर्याप्त होगा। एकल न्यायाधीश द्वारा नोट की गई चिंता के रूप में, नियम को तुच्छ मुकदमेबाजी बनी रहनी चाहिए और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा स्थापित मुकदमेबाजी से बचना चाहिए, लेकिन न्याय के विचारों की कीमत पर नहीं।

28. प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर, हम पाते हैं, किसी भी मामले में, मूल याचिकाकर्ता/प्रबंधन समिति/अपीलकर्ता ने एकल न्यायाधीश द्वारा नोट की गई कानून की आवश्यकता का अनुपालन किया था। इस प्रकार, भले ही उक्त प्रबंधन समिति के प्रबंधक श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ला द्वारा प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिका को बनाए रखने के लिए प्रबंधन समिति के एक प्रस्ताव को न्यायालय के समक्ष पेश करने की आवश्यकता थी, कि संकल्प दिनांक 13.01.2026 को मौजूद था जैसा कि पूरक हलफनामे के माध्यम से अभिलेखों पर लाया गया था। उस हद तक, एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि संकल्प श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ला को अधिकृत नहीं करता है, सही प्रतीत नहीं होता है।

29. श्री आर. के. ओझा द्वारा प्रस्तुत अंतिम सबमिशन के रूप में, उपरोक्त पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम रजिस्ट्री को जारी किए गए निर्देशों को इस आशय के लिए संशोधित करते हैं:

- (i) सभी शपथपत्रों (प्रथम शपथ पत्र, प्रतिशपथ पत्र, प्रत्युत्तर शपथ पत्र, अभियोग आवेदन, आदि) में प्रबंधन समिति द्वारा या उसकी ओर से भविष्य में दायर की जाने वाली सभी याचिकाओं में, उस व्यक्ति के अधिकार का खुलासा किया जा सकता है जिसके माध्यम से ऐसी प्रबंधन समिति न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है, प्रशासन की योजना के पहले पृष्ठ और प्रशासन की योजना के प्रासंगिक



खंड को संलग्न करके प्रकट किया जा सकता है जो ऐसे व्यक्ति को ऐसी कार्यवाही शुरू करने या ऐसा शपथपत्र दायर करने के लिए अधिकृत करता है, प्रबंधन समिति की ओर से दायर किए जाने वाले पहले हलफनामे में।

(ii) केवल उस स्थिति में, जब प्रशासन की योजना ऐसा प्राधिकार नहीं देती है, तो किसी भी प्राधिकारी को न्यायालय में आने वाले व्यक्ति के अधिकार को स्थापित करने के लिए प्रबंधन समिति का एक उचित संकल्प दायर किया जा सकता है, साथ ही प्रबंधन समिति की ओर से दायर किए जाने वाले पहले हलफनामे के साथ।

(iii) जहां ऐसा प्राधिकारी आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता है, न्यायालय की अनुमति के साथ इसे प्रस्तुत करने के लिए समय मांगते हुए उपयुक्त आवेदन दायर किया जा सकता है।

31. ऊपर बताए गए तीन तरीकों में से किसी एक का अनुपालन किए जाने के अधीन, रजिस्ट्री कार्यवाही को अपने उचित नोट/रिपोर्ट के साथ न्यायालय तक पहुंचने की अनुमति देगी।

32. हम स्पष्ट करते हैं, यह निर्देश संभावित रूप से, यानी 06.04.2026 से इस न्यायालय के समक्ष स्थापित या लाई जा सकने वाली कार्यवाही में प्रभावी किया जाना है।

33. तदनुसार, तत्काल इंट्रा-कोर्ट की अनुमति दी जाती है और दिनांक 17.02.2026 के आक्षेपित आदेश को रद्द/अपास्त किया जाता है। रिट याचिका को उसकी मूल संख्या-और स्थिति में बहाल किया जाता है। इसे 08.04.2026 को एक नए मामले के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

(न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी)

(न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)

मार्च 31, 2026

अनुराग/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।